



मरती नदियां, उणड़ता बुन्देलखण्ड

असमय मौत के मुंह में चली गई बन्डई ललितपुर जनपद के मड़वरा वन प्रभाग क्षेत्र की यह नदी जीव-जन्तु और आदिवासियों की जीवन का एक मात्र सहारा थी, यह सहारा उनसे छिन जाने के कारण सिर्फ आदिवासियों को ही नहीं अपितु वनजीवन को भी गहरा धक्का था। इस वन प्रभाग में रहने वाले जंगली जानवर सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन करने के लिए विवश हो गये हैं। बन्डई नदी की यात्रा भले ही लम्बी नहीं थी लेकिन इस नदी ने मड़वरा ब्लॉक के उस वन क्षेत्र में जहां जाने से लोग डरते थे, वहां के जंगली जानवरों को हमेशा ही जीवन दिया था। आज मृत हो चुकी बन्डई नदी पर शोक गाथा लिखने का असर हुआ और इसने इस संवाददाता को शासन में पैरोकारी और स्वयंसेवी संगठन के वासुदेव को प्रेरित किया। सब के सहायोग से सरकार ने नदी को जिन्दा किया है।

अपको बचपन याद होगा कि नदी में पानी बहता हुआ आवाज करता था, जिसे सुनकर हम खुशी से झूम उठते थे, लेकिन आज सैकड़ों गांवों की नदियां जाने कहां गुम हो गई हैं? बारिश कम हुई, नदी में कचरा डालने, मिट्टी जमा होने से उसकी गहराई प्रभावित हुई और नदी के आस-पास बस्तियों की वजह से उसे पाटने का काम भी किया गया। ऐसे में सभी को यह लगता है कि गांव में अगर नदी वापस आ जाए तो क्या मजा आ जाए! जी हां, पानीदार इलाका बुन्देलखण्ड के लोगों के मन में यही बात घुमड़ रही है।

इत चंबल उत नर्मदा, इत यमुना उत टोंस, नदी के सीमा में बसने वाला क्षेत्र बुन्देलखण्ड तेजी से रेगिस्तान बनने की दिशा में अग्रसर है। केन और बेतवा को जोड़ कर इस क्षेत्र में पानी लाने की योजना मुश्किलों में फस गई है। चन्देलकालीन हजारों तालाब बुन्देलखण्ड के भूगर्भ जल स्रोत को मजबूती प्रदान करते थे जो दो दशक में भूमाफियाओं की भेंट चढ़ गये हैं जिसके कारण अकाल की विभीषका से जूझ रहे बुन्देलखण्ड में सरकारी पैकेज से कुछ नहीं बदला। भोपाल के ताल से निकलने वाली बुन्देलखण्ड की धड़कन बेतवा नदी के साथ हो रही छेड़-छाड़ से इस नदी पर संकट के बादल

गहरा गये हैं। रायसेन के पास शराब फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण के कारण नदी व जल जहरीले हो रहे हैं। चन्देलकालीन तालाबों को सुखाने में स्थानीय लोगों का स्वार्थ का एक किस्सा महोबा के तत्कालीन जिलाधिकारी रहे अनुज झा ने मुझे सुनाया था कि किस तरह सूखे से जूझ रहे लोगों के लिए तालाब भरने के प्रयास को असफल करने की कोशिश श्री झा की सूझ-बूझ से पूरी नहीं हो पाई थी।

झांसी जनपद के ओरछा घाट से लेकर जालौन के कदौरा व भेड़ी के अलावा हमीरपुर के 50 स्थानों पर मौरंग खनन का कार्य होता है। हर साल बरसात के

पहले बेतवा के घाटों से निकालकर मौरंग को सड़क के किनारे उपजाऊ जमीन पर इकट्ठा कर लिया जाता है। बरसात में नदी में पानी आ जाने से घाट बंद हो जाते हैं तब यही भंडार बेचकर भारी मुनाफा कमाया जाता है। जनपद में चंजैत, मोहाना पौथिय, कलाली, शंकरि पीपर, कनौटा, पतारा, बेरी, सैन्ट्रल आदि प्रमुख खदानें हैं। इनसे प्रतिदिन पांच हजार ट्रक मौरंग का खनन होता है।

मार्च से शुरू होकर नवम्बर माह तक यह मौरंग खेतों में पड़ी रहती है। इसे उठाने के लिए ट्रकों की धमा-चौकड़ी होती है और सैकड़ों एकड़ जमीन रौंद दी जाती है जिससे वह भी अनुपजाऊ हो जाती है। सड़क से खदान घाट तक जाने के लिए रास्ते में पड़ने वाले सभी खेतों से ट्रक गुजरने का कोई रास्ता नहीं होता लिहाजा मौरंग व्यापारी खेतों के बीच से रास्ता लेने के लिए किसानों को अच्छी खासी रकम का भुगतान एक मुश्त कर देते हैं। इसके बाद सड़क के किनारे मौरंग जमा करने के लिए किसानों की कृषि योग्य भूमि भी सालाना की दर से व्यापारी ले लेते हैं। किसान इकट्ठा रूपये मिलने के लालच में इस जमीन को जोते बोते नहीं हैं।

लगभग दो दशकों से यही हालात बने रहने से बेतवा की बेहद उपजाऊ कटार और उसके आस-पास की कई सौ एकड़ जमीन अब पूरी तरह बंजर हो चुकी है। इस जमीन में मौरंग की परतें बिछ चुकी हैं। जिससे यह जमीन पूरी तरह कृषि के काबिल नहीं रह गयी है। जालौन तथा झांसी जनपद में धन लिप्सा के कारण सबसे बड़ा संकट बेतवा नदी पर है। बांदा जनपद के बंदौसा थानान्तर्गत ग्राम लमेहटा के बागै नदी में दिन-रात बालू का अवैध खनन हो रहा है। पहूज व बेतवा नदी के घाटों से बजरी महानगर में आने के साथ कानपुर व उरई तक पहुंच रही है। सबसे नजदीक पहूज नदी है, जो अवैध खनन करने वालों के निशाने पर है। इस नदी के उनाव बालाजी के पास बने घाट अवैध खनन का मुख्य क्षेत्र है। इसके साथ महानगर



बेतवा नदी के आस-पास की काफी जमीन मौरंग बिछने से बंजर हो चुकी है

की सीमा से निकली बेतवा नदी के विभिन्न घाटों से भी अवैध खनन किया जा रहा है। रामनगर घाट से तो डम्पर के डम्पर यहां आते हैं। महोबा जनपद में साल दर साल पड़ रहे सूखे से तालाबों में धूल उड़ रही है। मवेशी प्यास बुझाने के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं। यह हाल एक गांव का नहीं, बल्कि दर्जनों ऐसे गांव है जो पानी की विभीषिका बयान कर रहे हैं। मवेशियों की प्यास का अंदाजा शायद किसी को नहीं होता तभी तो बिना किसी शिकवा शिकायत प्यास से तड़प-तड़प कर उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ग्रामीण अंचलों में तालाबों में धूल के गुबार उड़ रहे हैं। खनन के काम पर नियमों की अवहेलना देखना हो तो बुन्देलखण्ड में आकर देखा जाये, यहां कोई भारत का संविधान लागू नहीं होता है। उच्च न्यायालय की बार-बार चेतावनी के बावजूद लिफ्टर की मदद से नदी की बची धारा तक से खनन का कार्य खुले आम हो रहा है। बेतवा नदी के

अस्तित्व पर सबसे अधिक संकट जालौन तथा हमीरपुर में देखने को मिल रहा है। यहां के एक हिस्से में नदी की जलधारा के बीच से ही खनन कार्य कराया जा रहा है। सिर्फ बेतवा ही नहीं केन, पहूच, सिन्ध, धसान, सुखनई, शहजाद, सजनाम, जामनी, सतार, बन्डई, बवेड़ी, यमझार, खैडर, मंदाकिनी, बागेन पर संकटों के पहाड़ टूट रहे हैं। असमय मौत के मुंह में चली गई बन्डई ललितपुर जनपद के मड़वरा वन प्रभाग क्षेत्र की यह नदी जीव-जन्तु और आदिवासियों की जीवन का एक मात्र सहारा थी, यह सहारा उनसे छिन जाने के कारण सिर्फ आदिवासियों को ही नहीं अपितु वनजीवन को भी गहरा धक्का था। इस वन प्रभाग में रहने वाले जंगली जानवर सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन करने के लिए विवश हो गये हैं। बन्डई नदी की यात्रा भले ही लम्बी नहीं थी लेकिन इस नदी ने मड़वरा ब्लाक के उस वन क्षेत्र में जहां जाने से लोग डरते थे,

पास में केवटो का पुरवा बड़ी तरिया है वहां की कंचनिया ने कहा हमारे गांव का जीवन कैसे चलेगा। नदी के सूखते ही कुएं सूख गये, नदी में भरा पानी सड़ने लगा है। शिकायत के संदर्भ में भोले-भाले बुंदेलखण्डी कहते हैं कि मास्टर साहब लिखा-पढ़ी नहीं करत का करी? नारायणपुर हार में पशुओं को चराने आए दया राम ने कहा कि हमारे पूरे इलाके का पानी सूख गया है यहां पानी के सहारे से आए तो देख रहे हैं, नदी सूख गयी। पिछले कई वर्षों से आ रहे हैं लेकिन कभी कल्पना नहीं की थी कि मंदाकनी सूख जायेगी। नारायणपुर के श्याम सुन्दर, चंद्रप्रकाश ने कहा कि हम लोगों को अंहकार था कि नदी कभी नहीं सूखेगी, अब हमारा पूरा गांव भयभीत है, कहा कि कैसे खेती होगी अभी तो सबसे बड़ी समस्या है पशुओं के पानी की। नदी की दहारों में जमा पानी सड़ने लगा है।

वहां के जंगली जानवरों को हमेशा ही जीवन दिया था। आज मृत हो चुकी बन्डई नदी पर शोक गाथा लिखने का असर हुआ और इसने इस संवाददाता को शासन में पैरोकारी और स्वयंसेवी संगठन के वासुदेव को प्रेरित किया। सब के सहयोग से सरकार ने नदी को जिन्दा किया है। इसी तरह दूसरी नदी चन्द्रावल को एक दशक बाद फिर से जिन्दा किया गया है। मंदाकनी नदी चित्रकूट का जीवन स्रोत है। आज स्थिति यह है कि मंदाकनी नदी का जीवन स्रोत पानी मंदाकनी से दूर हो गया है। पानी राजापुर की ओर नहीं जा रहा। नदी में एक तरफ पानी है दूसरी तरफ सूखी सिसकती मंदाकनी नदी धैवैन, चंदागाहना बनकट गांव से नदी का सूखना प्रारंभ हो जाता है, पास में केवटो का पुरवा बड़ी तरिया है वहां की कंचनिया ने कहा हमारे गांव का जीवन कैसे चलेगा। नदी के सूखते ही कुंए सूख गये, नदी में भरा पानी सड़ने लगा है। शिकायत के संदर्भ में भोले-भाले बुंदेलखण्डी कहते हैं कि मास्टर साहब लिखा-पढ़ी नहीं करत का करी? नारायणपुर हार में पशुओं को चराने आए दया राम ने कहा कि हमारे पूरे इलाके का पानी सूख गया है यहां पानी के सहारे से आए तो देख रहे हैं, नदी सूख गयी। पिछले कई वर्षों से आ रहे हैं लेकिन कभी कल्पना नहीं की थी कि

मंदाकनी सूख जायेगी। नारायणपुर के श्याम सुन्दर, चंद्रप्रकाश ने कहा कि हम लोगों को अंहकार था कि नदी कभी नहीं सूखेगी, अब हमारा पूरा गांव भयभीत है, कहा कि कैसे खेती होगी अभी तो सबसे बड़ी समस्या है पशुओं के पानी की। नदी की दहारों में जमा पानी सड़ने लगा है। आज नदी के सूखने का सबसे बड़ा कारण नदी में बांध है फिर सूरज कुंड में नया चेकडैम क्यों बन रहा है? सरकार हमारी राय क्यों नहीं लेती। इंजीनियरों ने नदी सुखाई है। इसलिए नदी पहली बार मृत हो रही है। मृत हो रही मंदाकनी को पुनर्जीवित करने के लिए सभी को मिलकर सोचना होगा। वैसली नदी काली पहाड़ी क्षेत्र के पश्चिम से निकलती है और सुपावली तक यह उत्तर दिशा में बहती है। इसमें कई बरसाती नदी नाले मिलते हैं। सुपावली के आगे यह मुरार नदी में संगम करती है। इन दोनों नदियों का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है। वैसली सिंध नदी की सहायक नदी हुआ करती थी। सिंध नदी ग्वालियर में आर-पार बहने वाली नदी है। यह विदिशा जिले में सिरोंज के मालवा पठार से निकल कर दक्षिण में ग्वालियर में प्रवेश करती है। इसके मार्ग में पारवती, नून, जोर, छछून्द नदी और कई बरसाती नाले इसमें मिलते हैं। उत्तर पूर्व में करीब दो सौ मील

बहने के बाद यह यमुना में संगम करती है। पारवती नदी शिवपुरी जिले से निकल कर नरवर के पास ग्वालियर में प्रवेश करती है। यहां इस नदी पर एक बांध बांधा गया है जो हरसी बांध के नाम से प्रसिद्ध है। शिवपुरी से जिस स्थान पर यह ग्वालियर में प्रवेश करती है, वहां भी इसका पानी बांधा गया है, जो ककेटो बांध के नाम से प्रसिद्ध है। पारवती डबरा के पास पवाया गांव में सिंध नदी से संगम करती है। नून पनिहार गांव के पास से निकल कर दक्षिण में बहने के बाद पूर्व की ओर मुड़ जाती है और सिंध में मिल जाती है। छछून्द नदी आंतरी के पास पूर्व में पहाड़ी से निकल कर दक्षिण की ओर बहती है और आगे सिंध से संगम करती है। सामाजिक संगठन केन बेतवा गठजोड़ के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं उनका कहना है कि प्राकृतिक नदियों का ऐसा अनर्गल गठजोड़ मौन एवं जंगलों को शांत खड़े बुन्देलखण्ड को विनाश एवं आने वाली कई पीढ़ियों के लिये जल त्रासदी की ओर ले जाने का निर्णायक गठजोड़ है। केन-बेतवा नदी गठजोड़ परियोजना है। बुन्देलखण्ड में बड़ी बांध परियोजनाओं यथा केन बेतवा लिंक, अर्जुन सहायक बांध परियोजना महोबा, बांदा, हमीरपुर प्रस्तावित क्षेत्र से विस्थापित किसानों को उचित मुआवजा एवं



नदियों को कल-कल बहने दो, लोगों को जिंदा रहने दो

पुनर्वास की माकूल व्यवस्था की जाये। “नदियों को कल-कल बहने दो, लोगों को जिन्दा रहने दो” बेतवा व चम्बल क्षेत्र में मछुआरों पर संकट भारी साबित हो रहा है। यह बात झांसी में जन्तु विज्ञानियों व विशेषज्ञों ने संगोष्ठी में कही है। उनका मानना है कि मछलियों व जलजीवों पर बुन्देलखण्ड में मंडरा रहे खतरे पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। बेतवा व चम्बल की सहायक नदियों का प्रवाह सिकुड़ने से उत्पन्न समस्या पर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो वह क्षेत्र रेगिस्तानी टीले में बदल सकता है। उमेश शुक्ल झांसी ने बुन्देलखण्ड स्तर पर जल जैव विविधता में हो रहे बदलाव को खतरनाक बताया। भोपाल के प्रो. डी.के. बेलसार ने बुंदेलखण्ड में नदियों में कम हो रहे पानी से मछुआरों को हो रही दिक्कतों पर चर्चा करते हुए कहा कि जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त मात्रा में मछलियों की उत्पादन न होने से मछुआरों के अलावा जल में रहने वाले अनेक जीवों के लिए भी संकट बढ़ गये हैं। प्राकृतिक पूंजी की उपेक्षा तेंदुरा के सुरेश रैकवार को नागवार गुजरी और वह 10 वर्षों से जल-जंगल-जमीन के संरक्षण अभियान में जुटे हैं। श्री रैकवार 20 वर्ष की अवस्था से पानी वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त राजेंद्र सिंह और पर्यावरण संरक्षक डॉ. जी.डी. अग्रवाल के नेतृत्व में पानी के लिए तरसते अलवर (राजस्थान) में 2002 तक काम किया। तत्पश्चात 2003 से उनके मार्गदर्शन में बुंदेलखण्ड में नदी बचाओ तालाब बचाओ का

अभियान छेड़ रखा है। समाजसेवी सुरेश रैकवार कहते हैं कि मुझे सूखती हुई नदियां, मिटते तालाब तथा इनके किनारे रहने वाली आवादी के छिन्ते अधिकारों की चिंता है। हमारी संस्कृति हमारी पहचान कहीं न कहीं जल चक्र की नियामक धारा से जुड़ी है। अपने जलस्रोतों को सहेजना धर्म भी है ताकि प्राणरक्षक तत्वों का प्रवाह हमारे जीवन में शाश्वत बना रहे। प्रदूषित हो रही पतित पावनी मंदाकिनी को साफ करने का बीड़ा युवाओं ने उठाया है। मंदाकिनी और केन में गहरा रहे जलसंकट के कारण आने वाले समय में बुंदलेखण्ड के लोग बिन पानी मर जाएंगे। फिल्म अभिनेता तथा बुन्देलखण्ड राज्य के लिए संघर्ष करते रहे राजा बुन्देला कहते हैं कि बुन्देलखण्ड की सदा नीरा नदियां लापरवाही के कारण मर गई हैं। इसका असर कृषि के साथ-साथ नागरिक जीवन पर भी पड़ा है। बुन्देलखण्ड के पहाड़ नंगे हो गए हैं और जमीन बंजर। इसके चलते बीहड़ों का विस्तार हो रहा है और खेत खलिहानों के साथ गांव भी उजड़ रहे हैं मूल रूप से नदी और कुएं कभी नहीं मरते, आदमी ही उसे मरा समझ लेता है। प्रयास किए जाएं तो इन नदियों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। ऐतिहासिक कुएं और बावड़ियों को भी री-चार्ज करके उनका पानी उन्हें लौटाया जा सकता है। लेकिन भगीरथ बनने को कोई तैयार नहीं है। बुंदेलखंड की अस्मिता नदियों-तालाबों और जल-जंगल-जमीन से जुड़ी है। सरकारों व आधुनिक समाज की उपेक्षा से बुंदेलखण्ड की

प्राकृतिक संपदाओं पर अस्तित्व बचाये रखने का खतरा मंडरा रहा है। परिणामस्वरूप नदियां व तालाब अंतिम सांसे गिन रहे हैं।

बोल्लिया में पानी के निजीकरण के विरोध में पनपा जनसंघर्ष क्रांति की वजह बना, पानी के माध्यम से हुए आमूलचूल राजनीतिक परिवर्तन का वक्त आ गया है। मरती नदियां उजड़ता बुन्देलखण्ड जल संकट का परिणाम ही है। भारत में पानी के निजीकरण की जोरदार वकालत की जा रही है। ऐसे में यहां के लोगों को भी बोल्लिया की जल क्रांति से सबक लेना चाहिए। उस देश में जहां हर चीज का निजीकरण हो गया था और सरकार भी शहरी ताकत से संचालित थी वही बोल्लिया अब ऐसे देश में तब्दील हो गया है जो अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखता है, अपने धन का प्रबंधन करता है और अपनी जनता की भलाई के लिए काम करता है। जल कार्यकर्ता और संयुक्त राष्ट्र में बोल्लिया के पूर्व राजदूत बाब्लो सोलोन ने भारत दौर के दौरान कहा, जलप्रदाय करने वाली निजी कंपनियों को खदेड़ने के लिए बोल्लिया के लापाज शहर में 1997 में और कोचाबांवा में 1998 में पानी के निजीकरण विरोधी संघर्ष शुरू हुआ था, जो कई सालों तक लगातार चला जिसमें तीन जांनें गईं और सैकड़ों महिला-पुरुष जख्मी हुए। आंदोलन की वजह थी निजी कंपनियों द्वारा पानी की लूट। पानी की इस लूट की कीमत वहां की जनता चुकाती थी। वे देश के बुनियादी संसाधनों का उपयोग कर सिर्फ मुनाफा ही कमाना चाहते थे। कोचाबांवा में उनका (कंपनियों का) पहला काम था 300 प्रतिशत जल दरें बढ़ाना। इससे लोग सड़कों पर आ गए थे। बोल्लिया में पानी को धरती माता का खून माना जाता है इसलिए पानी के निजीकरण से आम आदमी गुस्से में था। गैस, बिजली, रेलवे सबका पहले से ही निजीकरण हो चुका था। लेकिन जब निजी कंपनियों के लिए जल क्षेत्र भी प्रस्तावित कर दिया गया तो इससे लोग उत्तेजित हो गए, वे संगठित हुए और अपने संसाधनों को वापस प्राप्त करने की मांग करने लगे। कंपनी को जो पैसा दे सकता था, उसे अच्छी सेवाएं देने की कंपनी की नीति ने गरीबों को अलग-थलग कर दिया। इस नीति का परिणाम यह हुआ कि लोग पानी की गुणवत्ता और संसाधनों में समानता के अधिकारों की मांग करने लगे। निजी कंपनियां बुनियादी ढांचे और उन्हें प्राप्त संसाधनों जैसे-बांध, शुद्धिकरण संयंत्रों की भी देखभाल नहीं कर रही थीं इसके वाकजूद निजी कंपनी ने लापाज शहर से साल भर में 30 लाख डॉलर की कमाई की। इस घटना से जन आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। लोग सड़कों पर आ गए। जन आंदोलन ने

“नदियों को कल-कल बहने दो, लोगों को जिन्दा रहने दो” बेतवा व चम्बल क्षेत्र में मछुआरों पर संकट भारी साबित हो रहा है। यह बात झांसी में जन्तु विज्ञानियों व विशेषज्ञों ने संगोष्ठी में कही है। उनका मानना है कि मछलियों व जलजीवों पर बुन्देलखण्ड में मंडरा रहे खतरे पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। बेतवा व चम्बल की सहायक नदियों का प्रवाह सिकुड़ने से उत्पन्न समस्या पर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो वह क्षेत्र रेगिस्तानी टीले में बदल सकता है। उमेश शुक्ल झांसी ने बुन्देलखण्ड स्तर पर जल जैव विविधता में हो रहे बदलाव को खतरनाक बताया। भोपाल के प्रो. डी.के. बेलसार ने बुंदेलखण्ड में नदियों में कम हो रहे पानी से मछुआरों को हो रही दिक्कतों पर चर्चा करते हुए कहा कि जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त मात्रा में मछलियों की उत्पादन न होने से मछुआरों के अलावा जल में रहने वाले अनेक जीवों के लिए भी संकट बढ़ गये हैं।



सूखी धरती की कोख

शहर बंद करवा दिया तथा किसी के भी शहर में आने तथा बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। पहले सरकार ने लोगों का दमन किया, जिससे इस दौरान कुछ लोगों की जानें भी गईं। लेकिन बाद में सरकार को झुकना पड़ा और वह निजी कंपनियों के साथ हुए अनुबंधों को खत्म करने के लिए राजी हुई। निजीकरण को हटाने वाले जन आंदोलन का प्रभाव स्थानीय राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए नींव का पत्थर साबित हुआ। इसके तहत बोलिवियावासी अपनी सरकार चुनने के लिए आगे आए। पहली बार मूल निवासियों ने अपनी ताकत पहचानी और वोट के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपना राजनीतिक संगठन बनाने का निर्णय लिया। 2005 में पहली बार हमेशा की तरह 30 प्रतिशत के बजाय 54 प्रतिशत मतदान हुआ। सोलोन ने भारत से आग्रह किया है कि वह बोलिविया के अनुभव से सीख ले तथा जल क्षेत्र में पब्लिक-प्रायवेट-पार्टनरशिप से बचे। उनका मानना है कि पानी जनता का धन है, इसीलिए इसे निजी कंपनियों के मुनाफे का स्रोत नहीं बनने देना चाहिए। बुन्देलखण्ड में जल संकट के प्रति समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिन भयानक होंगे।

‘सूखती धरती की कोख भरने के लिए नाप-जोख। कई वर्षों की यातना संघर्ष विडंबना मिला नहीं हर्ष। उम्मीदों का नया दौर कहां था पता नहीं छोर। राह में है कितने रोड़े कहीं ज्यादा कहीं थोड़े। नियति ही बनी तबाही कही किसी से नहीं जाही। किये मुतकरे तो प्रयास हुआ फिर भी नहीं खास। नगाड़े बजना हुआ बंद फायदा ले गये कुछ चन्द। वाक की निवारक वार्ता सन्नाटा अब पाव पसारत। जीवन से दूर होता जल न जाने अब कैसा हो कल।

मौत के जबड़ों में फसे हैं हम आज नहीं तो कल होंगे कम। प्रदूषण ने पसार लिए पांव जहरीले हो गए धूप-छांव। धुएं से घुट रहा सब का दम प्रदूषण क्यों नहीं हो रहा कम। विनाशक परिवर्तनों के संकेत ऋतुएं बदली तो उजड़े खेत। अनियोजित औद्योगिक विकास कालाहांडी बना रहा आस-पास।

संपर्क करें:

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
ए-305 ओ.सी.आर. बिल्डिंग
विधानसभा मार्ग, लखनऊ
मो. 9415508695